[Shsi Ajit Bag]

crores for the Second Hooghly Bridge this year. Now the Second Hooghly Bridge Commission is in dire need of Rs. 11 crores immediately in order to release a huge quantity of imported steel from the dock within a few days. Under these circumstances I urge upon the Government to release Rs. 11 crores immediately to the Second Hooghly Bridge Commission without any delay so that the project work could not be hampered.

(iii) Need for a halt station at Burhanpue for Jhelum Express and Mahanagari Express

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा): सभापति महोदय, पिछले 30 वर्ष में बुरहानपुर से वाराणसी एवं दिल्ली से आने जाने के लिए कोई नई ट्रेन नहीं बढ़ी है। इस बीच में अभी-अभी 2 नई ट्रेन बम्बई से जम्मू-तवी (झेलम एक्सप्रेस) और बम्बई से वाराणसी (महानगरी एक्सप्रेस) शुरू हुई हैं परन्तु दोनों ही ट्रेन बुरहानपुर नहीं रुकती हैं।

बुरहानपुर मध्य प्रदेश का 11वें नम्बर का महत्वपूर्ण शहर है, नगर निगम है। 17,000 पावरलूम चलते हैं, 28 साइजिंग हैं, 5 कलैंडरिंग प्लान्ट हैं, स्पिनिंग मिल, वीविंग मिल हैं, कपास उत्पादन का बड़ा केन्द्र है, 14 करोड़ रुपये का केला प्रतिवर्ष बुरहानपुर से बाहर भेजा जाता है।

मुसलमानों, बोहरों, सिखों, हिन्दुओं का तीर्थ-स्थान है, ऐतिहासिक पर्यटन-स्थल है, मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, कबीर पंथियों के मंदिर हैं। बुरहानपुर से दिल्ली, मनमाड, पूना का काफी ट्रैफिक है। बुरहानपुर से वाराणसी का भी काफी ट्रैफिक है। अतः रेलवे मंत्री जी से निवेदन है कि (1) झेलम एक्सप्रेस (2) महानगरी एक्सप्रेस को बुरहानापुर में रोका जाये।

(iv) Pension benefit for retired Seamen.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): The Seafarers Welfare Fund Society of the Government of India has instituted pension benefits of Rs. 85/- per month to registered Indain Seamen whose registration has been cancelled on or after January 1, 1975. This has been a great relief not merely to the Seamen concerned but also to their families and dependents. However, this pension is denied to those who retired or were declared physically unfit before 1975. This discrimination does not appear to be logical or equitable. It may be recalled that in case of Seamen who retired prior to January 1975 their working conditions were much harsher and particularly before 1964, duty hours, over-time, double pay on paid holidays, Provident Fund and such other amenities were not even heard of. I therefore, urge Government to extend the above pension benefits also to those Seamen who retired before January 1, 1975. I further urge Government to look into the unsatisfactory manner of recruitment and conditions of service of Seamen and unemployment prevailing among them and to evolve a comprehensive strategy to provide a better deal to this section of our population.

(v) Need for resumption of Madurai edition of the Tamil Daily "Makkal Kural"

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): The Tamil Daily 'Makkal Kural" (Voice of the People which is boasting as a champion of the working class has closed the Madurai edition illegally by throwing many workers and their familes to the streets. The owner who is also the President of Indian Federation of Working Journalists, has opted lockout without proper remunerations.

While Palekar's award has been implemented by other Tamil Dailies in Tamil Nadu, *Makkal Kural*, has completely denied the rights of the workers. Further, the Management had indulged in violation of the Customs Act by giving false declaration with regard to import of printing machine from U.S.A.

The Management has totally rejected conciliation with workers. I, therefore, request the Minister for labour to interfere in this matter to lift the lockout and to resume the Madurai edition without any victimisation and save the workers from starvation.

(vi) Increase in number of dacoities, murders and lootings in Saidpur (U.P.)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सैदपुर की अत्यन्त विषम स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सैदपुर क्षेत्र में डकैती, हत्यायें, फर्जी मुठभेड़, लूट-पाट की इतनी घटनायें हो रही हैं कि यह अब दूसरा चम्बल बनने जा रहा है। यहां पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की कथित हत्यायें हो रही हैं। गत 3 माह में लगभग 20 यादव गोली से उड़ा दिए गए।

मान्यवर, मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में माननोय गृह मंत्री जी का ध्यान इधर ले जाते हुए कहूंगा कि सैदपुर तीन जिलों, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, को मिला कर बना एक संसदीय क्षेत्र है। यहां के रहने वाले 80 प्रतिशत हरिजन कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हैं। आज यहां का हर आदमी भयभीत है, आतंकित है। उसका सड़क पर चलना दूभर हो गया है। शाम की चिराग जलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। हत्यारे और डकैत गोल बना कर खुले-आम घूमते हैं।

अन्य प्रान्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, के भी शातिर अपराधी यहां भारी संख्या में अपना अड्डा बना रहे हैं। अन्य प्रान्तों से तस्करी करने वाले गिरोह भी यहां अफीम आदि का क्षेत्र होने की वजह से अपना जाल बढ़ाते चले जा रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री जी तुरन्त इस मामले की गंभीरता को महसूस करें। इसे रोकने की दिशा में कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करें एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हिदायत दें कि वे इस सैदपुर को दूसरा चम्बल होने से अविलम्ब रोकें।

(vii) Need to include Desi varieties of tobacco also under the provisions of Tobacco Board Act.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति महोदय, देश में कई प्रकार की तम्बाकू पैदा की जाती है, लेकिन तम्बाकू बोर्ड एक्ट में सभी प्रकार की तम्बाकू को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ वरजीनिया तम्बाकू का ही कार्यभार यह बोर्ड चलाता है। देसी बीड़ी तम्बाकू, रोस्टीका और नाटु आदि प्रकार की तम्बाकू पकाने वाले किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है। उन्हें तो प्राइवेट व्यापारियों, दलालों के हाथ ही मरना होता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है। इस कारण व्यापारियों के संगठन द्वारा बहुत कम कीमत पर यह तम्बाकू खरीदी जाती है और इन के पैसे भी सालों बाद मिलते हैं और इन लोगों के साथ कई प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है। इन किसानों का इस तरह जो शोषण हो रहा है, उन्हें इससे बचाने के लिये वाणिज्य और कृषि मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वरजीनिया से अलग प्रकार की जो तम्बाकू देश में पैदा होती है, उन सब का तम्बाकू बोर्ड एक्ट में समावेश किया जाए। इस बारे में सरकार ने भी कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री मुखर्जी, की अध्यक्षता में टोबेको एक्सपर्ट ग्रुप की रचना की थी। उस ग्रुप ने भी ऐसी